जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 192 प्रभात बीकानेर, रविवार 2 फरवरी, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

'बजट में दिल्ली और बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है'

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् ने कहा, केन्द्रीय बजट का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का केन्द्रीय बजट असल में दिल्ली के मतदाता को लुभाने की कोशिश है।

अगर आप 7 लाख रुपए से 12 लाख रु. सालाना कमा रहे हैं तो आप टैक्स छूट के दायरे में आ जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वे लोग हैं जो हर माह 60 हजार से एक लाख रु. तक कमाते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ 3.2 करोड़ लोगों को ही लाभ हो रहा है और दिल्ली में तो यह संख्या और भी कम है।

- चिदम्बरम् ने आरोप लगाया, बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण, कृषि क्षेत्र के बजट आवंटन में कटौती की गई है।
- चिदम्बरम् ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बजट में कटौती को क्रूर कदम बताया।
- उन्होंने कहा, नई टैक्स प्रणाली में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, खासकर, उन्हें जो हर माह 60,000 से एक लाख रूपए तक कमाते हैं, लेकिन पैट्रोल, डीजल में जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई है।
- उन्होंने कहा, बेरोजगारी दूर करना सबसे अहम् मांग है, पर, रोजगार सृजन की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

लेकिन पैट्रोल, डीज़ल, जीएसटी और किसी अन्य मोर्चे पर ऐसी कोई राहत नहीं दी है जिससे आम आदमी को मदद मिल सके। बेरोजगारी दूर करने पर भी कुछ नहीं किया गया है जो कि मूलभूत मांग है।

बजट में बिहार का भी ध्यान रखा गया है जहां अगले वर्ष आम चुनाव होने हैं।

बजट का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना है ना कि देश की जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना।

चिदम्बरम् ने कहा अपना आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री नया विज़न देने में पूरी तरह से असफल रही हैं, वे आवश्यक सुधार भी नहीं कर पाई। पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पूर्वोत्तर के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में कटौती की गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित बजट से भी कटौती की गई है जो क्रूर कदम है।

जब बजट को रेटिंग देने के बारे में पूछा गया तो एक पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली व बिहार के मतदाता इसे हाई रेटिंग देंगे पर शेष भारत के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

'बजट से सशक्त बनेगा राजस्थान'

जयपुर, 1 फरवरी (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देगा। साथ ही, बजट में मेक इन इण्डिया से अब 'मेक फॉर वर्ल्ड' की अवधारणा के साथ देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा दी गई है।

उन्होंने कहा कि जनता का यह बजट भारत के जन-जन के भविष्य को निखारेगा तथा बजट से समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में राजस्थान के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।

बढ़ाने, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता देने एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव दिए थे, जिस पर केन्द्र सरकार ने बजट में मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान के कल्याण पर फोकस किया गया है। साथ ही, अन्त्योदय की अवधारणा पर काम करते हुए, समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

85 प्रतिशत आयकर दाता आयकर के दायरे से बाहर निकले

आयकर में राहत की घोषणा से सरकार को एक लाख करोड़ रूपए के राजस्व का नुकसान होगा

नयी दिल्ली, 01 फरवरी। धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के घरेलू उपभोग और निवेश को बढ़ावा देने वाला आम बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मध्यम वर्ग को आयकर में बड़ी राहत और कृषि, लघु एवं मझौले उद्योग क्षेत्र तथा नये उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा कर सुधारों को आगे बढ़ाने विशेष प्रावधानों की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक लक्ष्यों को भी बजट में विशेष तवज्जो दी और बिहार में एक नये हवाई अड्डे, मखाना बोर्ड और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की महत्वपूर्ण घोषणायें की जहां इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

वित्त मंत्री के व्यक्तिगत आयकर में रियायत के प्रावधानों से औसतन मासिक एक लाख रुपये तक की कमाई पर अब कोई कर नहीं देना पड़ेगा जिससे उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने वृद्धों को ब्याज से होने वाली आय तथा अचल संपत्ति के किराये से होने वाली आय पर टीडीएस कटौती की सीमा में वृद्धि का भी प्रावधान किया है। उन्होंने अगले सप्ताह नया आयकर सरलीकरण विधेयक पेश करने की घोषणा की है।

- केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारी आयकर राहत की घोषणा की, जिसके तहत साठ हजार रूपए से एक लाख रूपए मासिक आय वाले लोगों को आयकर नहीं देना होगा। इससे मध्यम वर्ग में खुशी देखी गई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना आठवां केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें दिल्ली और बिहार के चुनावों को मद्देनज़र कई घोषणाएं की गईं।
- वित्त मंत्री ने रक्षा बजट में वृद्धि करते हुए, इसके लिए 6.81 लाख करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।
- मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यम, लघु तथा अति लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है।

सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित नई कर संरचना मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा देकर उपभोग, बचत और निवेश को काफी बढ़ावा देगी। बजट में किये गये प्रस्ताव के तहत एक लाख रुपए तक मासिक औसत आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में किये गये इस प्रस्ताव से 24 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। हालांकि इससे सरकार का एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व कम हो जायेगा।

सीतारमण ने विनिर्माण क्षेत्र को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल बजट ने रेल्वे के आधुनिकीकरण पर प्रश्न चिन्ह लगाया

केन्द्रीय बजट में रेल्वे को गत वर्ष जितनी राशि ही आवंटित की गई है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी उन लोगों की निराशा कई गुना बढ़ गई है, जो यह मानकर चल रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्डिंग का 25 प्रतिशत हिस्सा रेलवे को दे देंगी।

वित्त वर्ष 2026 के लिये रेलवे को किया गया आवंटन 2.55 लाख करोड़ रूपया ही रखा गया है, जितना यह पिछले वर्ष था। लेकिन महँगाई सूचकांक को 5 प्रतिशत वार्षिक मानकर गणना की जाये तो यह आवंटन वास्तव में और भी नकारात्मक दिखाई देगा। रेलवे कम्पार्टमैंट (रोलिंग स्टॉक) खरीद तथा ट्रैक-नवीनीकरण जैसी महत्वपूर्ण चीजों और कार्यों के लिये किया आवंटन गतवर्ष की राशि के ही बराबर रखा गया है। बजट ने भविष्य के आधुनिकीकरण, जैसे डेलिकेटेड फ्रेट

- रेल्वे को गत वर्ष 2.55 लाख करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे।
- रेल्वे के आधुनिकीकरण की बड़ी-बड़ी घोषणाओं को देखते हुए इस वर्ष उम्मीद थी कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का 25 प्रतिशत रेल्वे को देगी, पर ऐसा नहीं हुआ।
- रेल्वे को 31,000 किलोमीटर रेल्वे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है और रेल दुर्घटना निरोधक तंत्र ''कवच'' भी स्थापित करना है, साथ ही मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन देना है। यह सब बजट प्रस्तावों में परिलक्षित नहीं हो रहा है।

कॉरिडोर्स के निर्माण की योजनाओं या नये रेल मार्गों के सेमी-हाई स्पीड तथा हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण आदि की आवश्यकता पर चुप्पी साध रखी है।

शुक्रवार को पेश किये गये ''इकोनॉमिक सर्वे'' में, सरकार ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा आँकड़े को स्वीकार किया था तथा जोर देते हुये कहा गया था कि इस वित्त वर्ष में इसे घटाकर 4.4 प्रतिशत करने की जरूरत है। इसलिये, सीतारमण के बजट प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। भारतीय रेलवे, जिसे हाल ही के वर्षों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर, 1 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त

- पॉक्सो कोर्ट ने 24 वर्षीय आरोपी युवक रोहित शर्मा पर 1.35 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

ने नाबालिग पीड़िता को जन्मदिन की पार्टी में ले जाने का बहाना बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बंदूक की गोली के घावों के लिए एक बैंड-एड जैसा है बजट'

राहुल गांधी ने यह टिप्पणी करते हुए कहा, वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हमारे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारी बदलाव की जरूरत है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जैसे ही बजट पेश करने के लिए खड़ी हुईं, कुछ विपक्षी नेता मौनी अमावस्या को महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा की माँग करते हुये ''प्रतीकात्मक वॉक आउट'' कर गये। वहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की पूरी कवायद पर प्रहार करते हुये, इसे ''बंदूक की गोली से लगे घावों के लिये बैन्ड-एड'' बताया तथा कहा कि केन्द्र ''विचारों और योजनाओं के मामले में दिवालिया'' है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के समाधान के लिये प्रतिमान-परिवर्तन की आवश्यकता है।

कुछ विपक्षी सांसदों, जिनमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल थे, ने लोकसभा से प्रतीकात्मक वॉक आउट किया। जब कुछ विपक्षी सदस्य विरोध-स्वरूप वॉक आउट कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के खिलाफ नारे सारी संसद में गूँज रहे थे।

- सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पेश किए जाने से पहले प्रयागराज में हुई भगदड़ पर चर्चा की मांग की और फिर प्रतीकात्मक वॉक आउट किया।
- कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मध्यम वर्ग को मिली टैक्स राहत की सराहना की, पर, बेरोज़गारी का उल्लेख नहीं करने पर चिंता जताई।
- शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा, बजट सिर्फ बिहार पर केन्द्रित है, पंजाब और इसके किसानों की उपेक्षा की गई है।

पूर्वान्ह 11 बजकर कुछ मिनट बाद, जैसे ही सीतारमण बजट पेश करने के लिये उठीं, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने नारेबाजी की तथा हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। वे माँग कर रहे थे कि सदन में सबसे पहले इस सप्ताह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ पर चर्चा की जाये।

अखिलेश यादव इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र- दोनों ही जगह सत्ता में है, के घोर आलोचक रहे हैं। वे पहले भी माँग कर चुके हैं कि राज्य सरकार इस धार्मिक भीड़ का प्रशासन तथा प्रबंधन सेना को सौंप दे।

कांग्रेस ने केन्द्रीय बजट की आलोचना करते हुये, इसे स्थिर वेतन की ''बीमारी'', व्यापक उपभोग में उल्लास की कमी, निजी निवेश की मंद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)